सीआरसी | बीआरसी | डाइट की बदली हुई भूमिका

शुचि दुबे

कोविड-19 महामारी ने बच्चों समेत समूचे मानवीय तंत्र को बेहद बुरी तरह से प्रभावित किया है। वे पारिवारिक, सामाजिक आदि कई तरीक़ों से तो प्रभावित हुए ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है उनकी शिक्षा। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर के स्कूल जाने वाले 90 फीसदी बच्चों की शिक्षा महामारी से बाधित हुई है।

ह्यूमन राइट्स वॉच[1] की रिपोर्ट में बताया गया है कि *कोविड-19* के कारण स्कूलों के बन्द होने से कैसे बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए क्योंकि महामारी के दौरान तमाम बच्चों के पास अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए ज़रूरी अवसर, साधन या पहुँच नहीं थी। रिपोर्ट में पाया गया कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा सम्बन्धी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। अनेक सरकारों के पास ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए ऐसी नीतियाँ, संसाधन या बुनियादी ढाँचा नहीं था जिससे कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सकें।

पृष्ठभूमि

बच्चों को शिक्षित करने की दशकों की धीमी लेकिन स्थायी गति मार्च 2020 में अचानक थम गई। अप्रैल तक नोवल कोरोनावायरस का प्रसार रोकने के लिए देश के करोड़ों विद्यार्थियों को उनके पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जाना बन्द करना पड़ा। बाद में देश के कुछ हिस्सों में कुछ विद्यार्थियों के लिए स्कूल फिर से खोले गए, जबकि अन्य जगहों पर स्कूलों में विद्यार्थियों की वापसी नहीं हो पाई है। स्कूल बन्द होने के दौरान ज़्यादातर स्थानों पर शिक्षा या तो ऑनलाइन या अन्य दूरस्थ तरीक़ों से प्रदान की गई, लेकिन इसकी सफलता और गुणवत्ता में भारी अन्तर है। इंटरनेट तक पहुँच, कनेक्टिविटी सुलभता, भौतिक तैयारी, शिक्षकों के प्रशिक्षण और घर की परिस्थितियाँ समेत कई मुद्दों ने दूरस्थ शिक्षा की व्यवहार्यता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच की सीनियर एजुकेशन रिसर्चर एलिन मार्टिनेज ने कहा, “महामारी के दौरान लाखों बच्चों के शिक्षा से वंचित होने के कारण अब समय आ गया है कि बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण एवं मज़बूत शिक्षा-प्रणाली का पुनर्निर्माण कर शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ़ महामारी से पहले की स्थिति बहाल करना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उन ख़ामियों को दूर करना होना चाहिए जिनके कारण लम्बे समय से स्कूल के दरवाज़े सभी बच्चों के लिए खुले नहीं हैं।”

लेकिन इस मुद्दे पर सरकारें और ग़ैर-सरकारी शैक्षिक संगठन दोनों ही बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। फ़ौरी तौर पर कुछ प्रयास तो हुए लेकिन वे प्रयास सुसंगत नहीं होने के कारण बहुत सफल नहीं हो सके। इसी कड़ी में भारत में भी कई राज्यों ने सरकारी प्रयासों से ऑनलाइन शिक्षण के साथ ही अन्य कई तरीक़ों से बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने की शुरुआत करने की कोशिश की। लेकिन वंचित और ग्रामीण परिवारों के बच्चों तक यह प्रयास नहीं पहुँच पाए क्योंकि वे पर्याप्त डिवाइस या इंटरनेट नहीं ख़रीद सकते थे। कम संसाधनों वाले स्कूलों, जिनके विद्यार्थी पहले से ही शिक्षा सम्बन्धी बड़ी बाधाओं का सामना कर रहे थे, ने डिजिटल सीमाओं के समक्ष अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में विशेष कठिनाइयों का सामना किया। शिक्षा-प्रणाली विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ऐसा डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने में अक्सर विफल रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विद्यार्थी और शिक्षक इन तकनीकों का आत्मविश्वास के साथ और सुरक्षित उपयोग कर सकें।

ऐसे विकट समय में शिक्षा के अकादमिक और प्रबन्धन के स्तर पर काम करने वाले सरकारी और ग़ैर-सरकारी शैक्षिक संगठनों की ज़िम्मेदारी में बढ़ोतरी हुई है। देश के शैक्षिक वर्ग, विद्यार्थी और अभिभावक इन संस्थानों की ओर हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, बीआरसी और सीआरसी जैसे संस्थान वर्तमान परिस्थितियों में अपनी भूमिका को अपडेट करने में प्रयत्नशील हैं। लेकिन करोड़ों बच्चे जो बग़ैर औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए निरन्तर दो सत्रों (2020-21, 2021-22) से प्रोन्नत होकर अगली कक्षा में जा रहे हैं, लर्निंग गैप की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या आगे कितने समय तक उनके साथ चलती रहेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लान बनाकर हरेक गाँव–देहात तक शिक्षा को सरल, प्रामाणिक और व्यवहारिक बनाने की ज़िम्मेदारी ज़िले से लेकर स्कूल स्तर तक की है। जो लोग या

संस्थाएँ किसी क्षेत्र विशेष के बच्चों के साथ निरन्तर काम कर रही हैं उन्हें योजना बनाते और उसे लागू करते समय उस क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए और समय-समय पर उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

सरकारी स्तर पर एससीईआरटी ने राज्य स्तर पर बच्चों को शिक्षित करने के ऑनलाइन तरीक़ों को अपनाया है। व्हाट्सऐप के माध्यम से वर्कशीट, वीडियो, क्विज़ आदि को बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक यह प्रयास कारगर भी सिद्ध हुए, लेकिन पहले बताई जा चुकी दिक़्क़तों के अलावा कुछ और दिक़्क़तें भी थीं। जैसे कि शिक्षण-सामग्री बच्चों के स्तर के अनुरूप नहीं थी क्योंकि इन सामग्रियों को तैयार करने से पहले बच्चों के शैक्षणिक स्तर का कोई आकलन नहीं किया गया था। साथ ही शिक्षण-सामग्री शिक्षकों की मदद के बिना तैयार की गई थी। क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। यह व्यवस्था एससीईआरटी के स्तर पर की गई थी और इसमें अन्य शैक्षिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष रूप से कोई दख़ल नहीं था। यही कारण था कि अन्य योजनाओं की तरह धरातल तक आते-आते यह कार्य अरुचिपूर्ण हो गए और व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं हो सका।

बहुत सारी सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ निरन्तर कई दशकों से शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वे अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से संचालित नहीं कर पाईं। जबकि आवश्यकता थी कि वे अपने ज़िले/क्षेत्र के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में बच्चों के लिए योजना बनातीं और काम करतीं।

सरकारी संस्थान

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institutes of Educational Training)

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) एक ज़िले के भीतर की शैक्षिक संस्थाओं और स्कूलों के लिए मार्गदर्शन के केन्द्रों के रूप में स्थापित किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित डाइट शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस है। डाइट को शिक्षण-अधिगम संसाधनों को बनाने और प्रदान करने, क्रियात्मक अनुसन्धान को बढ़ावा देने, गतिविधि-आधारित शिक्षा प्रदान करने, आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, अध्यापकों को मदद करने का काम सौंपा गया है। डाइट की ज़िम्मेदारियों में शिक्षण की शैक्षिक प्रौद्योगिकी से परिचय कराना और मूल्यांकन की आधुनिक विधियों से अवगत कराना भी शामिल है।

वर्तमान परिस्थितियों में डाइट अपनी इन्हीं भूमिकाओं को और अधिक समृद्ध करते हुए यदि शिक्षकों और बच्चों के साथ ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की योजना बनाए तो जिन बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षण की सुविधाएँ नहीं हैं, उनके लर्निंग गैप को कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

इसके लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं :

- पूरे ज़िले को भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर चिह्नित करना।
- चिह्नित क्षेत्रों के लिए वहाँ कार्यरत शिक्षकों का समूह बनाकर बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का आकलन करना।
- इस आकलन के आधार पर कम समयावधि के ऐसे कोर्सेस तैयार करना, जो बच्चों की विषयगत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जिनके पास ऑनलाइन संसाधन हों उन तक ऑनलाइन माध्यम से तथा अन्य बच्चों के पास शिक्षक को अपनी पहुँच बनाकर काम करना चाहिए ।
- शिक्षकों के साथ इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, बैठकों आदि के माध्यम से निरन्तर चर्चा करना ताकि समय–समय पर योजना की समीक्षा और आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा सकें।
- हरेक बच्चे के लिए तय किए गए प्लान के प्रभावी तथा समयबद्ध मूल्यांकन की व्यवस्था करना ताकि पता चलता रहे कि हरेक बच्चे के साथ किन लर्निंग आउटकम्स पर काम किया जाना शेष है।
- बच्चों के लिए उनके स्तर के अनुसार वर्कशीट आदि का निर्माण शिक्षकों की मदद से करना।
- इस पूरे प्लान में वर्कशीट, शिक्षण-अधिगम सामग्री, पुस्तकालय की पुस्तकें आदि को पर्याप्त स्थान देना होगा ताकि बच्चे शिक्षण के प्रभावी संसाधनों के रूप में इनका उपयोग कर सकें।
- इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों और गाँव के शिक्षित व्यक्तियों को भी सरल और व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक के रूप में तैयार करना होगा ताकि वे अपने परिवार, पड़ोस और मोहल्ले के बच्चों के साथ काम कर सकें।

इस प्रकार डाइट संस्थानों को अब वास्तविक रूप में लाइट हाउस का काम करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि डाइट शिक्षकों, बीआरसी, सीआरसी के अतिरिक्त शिक्षा में कार्य करने वाले अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि इस कार्य में सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सके।

ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (बीआरसी)

बीआरसी ब्लॉक स्तर पर ज़िला शिक्षा अधिकारी के साथ क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स (सीआरसी) से समन्वय करके यह सुनिश्चित करती हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाएँ विद्यालय स्तर तक पहुँचे, जैसे कि :

1. स्कूलों के भौतिक बुनियादी ढाँचे जैसे कि कक्षाओं, चारदीवारी, शौचालय आदि बनाने के लिए अनुमोदन करना।
2. जिन बच्चों के घर स्कूल से दूर हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का अनुमोदन करना।
3. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री और उपकरण प्रदान करना।

प्रत्येक बीआरसी में पाँच-छह सदस्य होते हैं, जो अपने ब्लॉक के विद्यालयों का निरन्तर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं। उनके अवलोकन सीआरसी के साथ साझा किए जाते हैं और इनके आधार पर योजना, प्रशिक्षण और शिक्षा में गुणवत्ता-सुधार की योजना बनाई जाती है।

बीआरसी के कार्यों में शामिल हैं :

- प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- विद्यालयों के कार्यों को सुव्यवस्थित करने एवं सुधारने के लिए सीआरसी को सहयोग करना।
- शिक्षा के अधिकार (आरटीई) क़ानून के अन्तर्गत प्रावधानों के क्रियान्वयन में एनजीओ एवं स्थानीय प्रशासन का सहयोग करना।

बीआरसी की अपने ब्लॉक में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बीआरसी अपने सदस्यों व अन्य संसाधनों को बच्चों के साथ काम करने में लगा दें तो बच्चों को फ़ायदा होता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में जब स्कूल बन्द हैं तो बीआरसी सामुदायिक कक्षाएँ प्रारम्भ करने के लिए अपने मानव संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही इन सामुदायिक कक्षाओं के लिए बच्चों के स्तर व आवश्यकता अनुसार सामग्री तैयार करने, बच्चों को पढ़ाने व समय-समय पर उनका आकलन करने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर सकती है।

वर्तमान परिस्थितियों में बीआरसी अपने इन्हीं कार्यों को अपडेट करते हुए डाइट के साथ समन्वय बनाकर बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करने का प्रयास कर सकती है। इससे स्कूल बन्द पर होने पर बच्चे जिस कक्षा में थे कम-से-कम उस कक्षा-स्तर को बनाए रखने में कुछ हद तक सफलता मिल सकती है।

इसके लिए बीआरसी को निम्न कार्य करने होंगे :

- डाइट व अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- *कोविड-19* से उत्पन्न हालातों में बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए इस पर शिक्षकों के साथ चर्चा करना और शिक्षकों के अनुभव के आधार पर मॉड्यूल बनाकर ऑनलाइन कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।
- स्कूलवार योजना बनाना ताकि सभी बच्चों तक शिक्षकों की पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर वर्कशीट व अन्य शिक्षण-सामग्री का निर्माण करना।
- विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के अनुभवों/समस्याओं को सुनकर सकारात्मक फीडबैक देना।
- बच्चों के शिक्षण का सही तरह से मूल्यांकन हो यह सुनिश्चित करना।
- गाँवों में वालंटियर हेतु छोटे प्रशिक्षण आयोजित करना। गाँव के शिक्षित युवा या वे जो हायर सैकेण्डरी के स्तर पर पर पढ़ रहे हों, उन्हें अपने पास-पड़ोस या मोहल्ले के बच्चों को प्रारम्भिक भाषा या गणित पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है।

क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (सीआरसी)

विद्यालयों के साथ कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली सभी शैक्षिक संस्थाओं से प्रत्यक्षत: सम्बद्ध सीआरसी ज़िला शिक्षा अधिकारी तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ निकटता से कार्य करती है। पंचायत मुख्यालय के उच्चतर विद्यालय को सीआरसी बनाया जाता है, जिसके अधीन उस पंचायत के समस्त विद्यालय होते हैं।

सीआरसी के कार्य हैं :

- कक्षा अवलोकन करना और कक्षा-कक्षीय शिक्षण में शिक्षकों को सम्बलन प्रदान करना।
- विद्यालयों में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों की मासिक बैठकें, प्रशिक्षण आयोजित करना।
- स्कूल प्रबन्धन समिति, अभिभावकों, अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

बदली हुई परिस्थितियों में सीआरसी स्कूल प्रबन्धन समिति, अभिभावकों और विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर गाँव में 3-4 स्थानों पर शिक्षकों एवं स्वयंसेवकों की मदद से बच्चों के लिए सामुदायिक कक्षाएँ आयोजित कर सकती है। इसके लिए हरेक बच्चे का प्री-टैस्ट लेकर योजना बनाई जा सकती है। शिक्षकों से परामर्श करके यह तय किया जा सकता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए।

सीआरसी शिक्षकों से यह चर्चा भी कर सकती है कि उपलब्ध संसाधनों की मदद से बच्चों को सीखने के कौन-से अवसर प्रदान किए जा सकते हैं ताकि वे भाषा और गणित के बुनियादी कौशलों को रोचक तरीक़े से सीख सकें। साथ ही उनके सीखने की निरन्तरता को भी सुनिश्चित किया जा सके। सीआरसी को स्थानीय भाषा में छोटी कविताएँ, कहानी आदि के चार्ट, छोटी कितबिया (बुकलेट) जैसी पाठ्यसामग्री निर्मित करने और इन्हें बच्चों तक पहुँचाने के लिए डाइट और अन्य शैक्षिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना चाहिए।

कुछ महत्त्वपूर्ण बातें

इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखना होगा कि शिक्षक उपेक्षित न हों। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि पाठ्यपुस्तक से लेकर वर्कशीट-निर्माण तक का कार्य राज्य की कोई एक या दो संस्थाएँ मिलकर करती हैं। तैयार सामग्री को तय समय में लागू करने के निर्देश देते हुए शिक्षकों तक पहुँचा दिया जाता है। इसमें शिक्षकों की कोई रुचि नहीं होती है और इसे वे केवल सरकारी आदेश मानकर पूरा कर देते हैं। यदि वर्कशीट-निर्माण, बच्चों को पढ़ाने के तरीक़ों जैसे कार्यों में शिक्षकों को स्वतंत्रता दी जाए तो शायद परिणाम ज़्यादा बेहतर और असरकारी होंगे। इसके लिए समय-समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा में काम करने वाले समस्त लोगों और संस्थाओं को अपनी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। ख़ासतौर पर *कोविड-19* के अनुभव के बाद हमें इस विषय पर शोध करना चाहिए कि अलग-अलग परिस्थितियों में हम बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं ।

डाइट, बीआरसी, सीआरसी के साथ ही स्कूलों को भी इसका विश्लेषण करना चाहिए कि कितने विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा और विद्यार्थियों में से कितनों ने स्कूल छोड़ा, कौन वापस आया और कौन नहीं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल वापसी कार्यक्रम पढ़ाई छोड़ने वाले सभी बच्चों की खोजबीन करे ताकि समस्त बच्चे जो पढ़ाई में पिछड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं वे अपनी उम्र के उपयुक्त कक्षा-स्तर तक पहुँच सकें। हमें उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति महामारी के कारण प्रभावित हुई है और वे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और उन बच्चों के बारे में भी जिनके माता-पिता *कोविड-19* के संक्रमण के डर से उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं।

ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ निम्न चीज़ें की जा सकती हैं :

1. स्कूल प्रबन्धन समिति/डॉक्टर/शिक्षकों और अन्य प्रभावशाली लोगों जैसे कि सरपंच और जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे बच्चों व अभिभावकों की काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि बच्चे स्कूल वापिस आ सकें।
2. बच्चों के वास्तविक कक्षा-स्तर और निर्धारित कक्षा-स्तर के बीच के अन्तराल को भरने के लिए बेसलाइन आकलन के आधार पर एक ब्रिज कोर्स तैयार किया जाना चाहिए।

Endnotes

i Years Don't Wait for Them: Increased Inequalities in Children's Right to Education Due to the COVID-19 Pandem-ic. https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid

ii NCERT: National Council of Educational Research and Training
SCERT: State Council of Educational Research and Training
DIET: District Institute of Educational Training
BRC: Block Resource Centre
CRC: Cluster Resource Centre



शुचि दुबे ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की है। 2014 में वह अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन के फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल हुईं और पाली ज़िले के बाली ब्लॉक में राजस्थान टीम के साथ काम किया। फेलोशिप पूरी करने के बाद उन्होंने 2020 तक गणित की समझ विकसित करने के लिए बाँसवाड़ा में शिक्षकों के साथ स्रोत व्यक्ति के तौर पर कार्य किया। मार्च 2021, से वह ज़िला संस्थान अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन, सिरोही के साथ प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उन्हें चित्र बनाना और बच्चों को कहानियाँ सुनाना बहुत पसन्द है। उनसे suchi.dubay@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।